आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 13.12.2025 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 491 जैंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बने।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में ''क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल'' का शुभारंभ किया।
- पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए।
- चम्पावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बिलाट सौंन तोक का दौरा किया। कहा– विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पासिंग आउट परेड

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड के बाद 491 जैंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके अलावा 14 मित्र देशों के 34 कैडेट भी आज पास आउट होकर अपने देशों की सेना का हिस्सा बने। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी ली। इस दौरान देशभक्ति के गीतों पर इन वीरों की कदमताल देखते ही बन रही थी। जनरल द्विवेदी ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया। देश के भावी सैन्य अधिकारियों ने जब भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरा तो, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। थल सेना प्रमुख ने नव–नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देते हुए युवा अधिकारियों के उच्च स्तर के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहनशक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने युवा अधिकारियों को भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के निर्वहन और निष्ठा, प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेना में कमीशन प्राप्त करना केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्य और निःस्वार्थ सेवा की शुरुआत है। यह न केवल भारत के रक्षा नेतृत्व को सुदृढ़ करती है, बल्कि मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक सैन्य सहयोग को भी सशक्त बनाती है।

क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में दून कल्चरल एंड लिटरेरी सोसायटी द्वारा आयोजित ''क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल'' का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल मात्र मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज, न्याय और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीर संवाद की राह खोलता है। उन्होंने कहा कि आज

अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, जिसमें साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, ड्रग्स से जुड़े मामले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग जैसे नए खतरे सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं के लिए तकनीकी जागरूकता के साथ ही नैतिक मूल्यों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल समाज में सतर्कता, संवेदनशीलता और नई सोच को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है। राज्यपाल ने पुलिस बल के समर्पण, कठिन परिश्रम और जनसेवा की भावना की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून–व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि समाज की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद, समझ और सहयोग बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश–भानियाबाला के बीच शिवालिक हाथी कॉरिडोर में सड़क चौडीकरण की जद में आ रहे 4 हजार 369 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए सचिव लोक निर्माण विभाग को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

जीएसटी संग्रहण

राज्य कर विभाग के हल्द्वानी सम्भाग में वस्तु एवं सेवा कर– जीएसटी संग्रह नवम्बर माह में 46 करोड़ 17 लाख रूपये रहा। हल्द्वानी सम्भाग की संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, राज्य कर, हेमा बिष्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष के नवम्बर माह की तुलना में इस वर्ष नवम्बर में जीएसटी संग्रह में 2 दशमलव 8–5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष नवम्बर में कुल जीएसटी संग्रह 44 करोड़ 90 लाख रूपये था। उन्होंने बताया कि जीएसटी संग्रह में नैनीताल जिले का योगदान सर्वाधिक 35 करोड़ 31 लाख रूपये रहा, वहीं बागेश्वर जिले में संग्रह सबसे कम कुल 71 लाख रूपये रहा। श्रीमती बिष्ट ने बताया कि इस बार सीमांत पिथौरागढ़ जिले से सर्वाधिक 31 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 4 करोड़ 69 लाख रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ।

बैठक पौड़ी

पौड़ी गढ़वाल के गुलदार प्रभावित इलाकों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने सभी विकासखंडों के शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने घर से स्कूल तक बच्चों की एस्कॉर्ट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश देते हुए इससे संबंधित अद्यतन जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया में नोडल विभाग रहेगा और समन्वय बनाते हुए सुरक्षा उपायों की निगरानी करेगा। उन्होंने उन विद्यालयों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, जहां एस्कॉर्ट व्यवस्था की सर्वाधिक जरूरत है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम प्रहरी

और वन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुरक्षा कदम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वन विभाग को सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने और पंचायती राज विभाग को स्कूली मार्गों व आसपास की झाड़ियों की तुरंत कटान कराने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर पर संवेदनशील विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी निरीक्षण

चम्पावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने चम्पावत विकासखंड की ग्राम पंचायत डिगडाई के बिलाट सौंन तोक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति और ग्रामीणों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं का आकलन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने चैन लिंक फेंसिंग, विधायक निधि से निर्मित सीसी मार्ग और गौशाला निर्माण कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं, ताकि उनका स्थायी लाभ आमजन को मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कई परिवारों के घरों का दौरा कर बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई और कृषि से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों की शिकायतों और सुझावों को सुनने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सम्मान

अल्मोड़ा जिले के सुरईखेत, द्वाराहाट के शिक्षक व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मोहन चन्द्र कांडपाल को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मान मिलने पर अल्मोड़ा के बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने उनका अल्मोड़ा में सम्मान किया। इस अवसर पर श्री कांडपाल ने कहा कि विश्व आज गम्भीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में "पानी बोओ–पानी उगाओ" अभियान को जन–आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने नदी–नालों, प्राकृतिक जल स्रोतों, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।

मलिन बस्ती बैठक

अल्मोड़ा जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के संबंध में जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण संबंधी नियमावली के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, उनका ड्रोन सर्वे करने के साथ ही प्रत्येक परिवार का चिन्हीकरण किया जाए। जो परिवार विनियमितिकरण के दायरे में हैं, उनके विनियमितिकरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह भी सर्वे किया जाए, कि मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के घर किस श्रेणी की भूमि पर

अवस्थित हैं और नियमानुसार इनको श्रेणीबद्ध किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सभी कार्य आगामी 15 दिन में संपन्न किए जाएं, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।